

इंदौर से पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चलेगी मेट्रो

75 मीटर चौड़ी सड़क में मेट्रो का प्रावधान

वीरेंद्र वर्मा
इंदौर. शहर के पश्चिम क्षेत्र में गांधीनगर इलाके से इंदौर पीथमपुर के बीच मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है. इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क योजना के ड्राफ्ट में इसका प्रावधान किया गया है. सबसे खास बात यह है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के बीच में मेट्रो के पियर खड़े करने के लिए अभी से कच्ची जमीन छोड़ी जा रही है. इनका ही नहीं एमपी मेट्रो ने भी उक्त सड़क के साथ पीथमपुर तक लाइन डालने के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है. एमपीआईडीसी ने यह भविष्य को ध्यान में रखकर सड़क के साथ मेट्रो का प्रावधान भी जोड़ा है, जिसे राज्य सरकार ने

मेट्रो रेल का पीथमपुर से जुड़ने का फायदा

इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के साथ मेट्रो रेल से पीथमपुर का जुड़ना बहुत फायदेमंद साबित होगा. एमपीआईडीसी के अधिकारियों की दूरदृष्टि का परिणाम है कि उन्होंने सड़क के साथ मेट्रो लाइन के लिए प्रावधान किया. केवल प्रावधान नहीं बल्कि उसके लिए बकायदा सड़क के सेंटर में जमीन भी अभी से छोड़ दी है. गांधीनगर से पीथमपुर इंटरस्टेशन एरिया मेट्रो से जुड़ने के बाद आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट और शहर में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भी कनेक्टिव मेट्रो रेल मिलेगी. एक बड़ा हिस्सा दो जिलों और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में मेट्रो नेटवर्क के लिए फायदा करेगा.

भी मंजुरी दी है.

पिछले दिनों राज्य सरकार ने इंदौर से पीथमपुर तक 19 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क का गजट नोटिफिकेशन किया है. उक्त सड़क में एमपीआईडीसी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सड़क के बीच

से एलिवेटेड मेट्रो रेल का प्रावधान किया है. इसके लिए सड़क बीच में 3.6 मीटर जमीन छोड़कर सड़क का निर्माण किया जाएगा. सड़क के दोनों मुख्य कैरेज के बीच एक एक हिस्सा भी मेट्रो के पियर खड़े करने के दौरान लगने वाली जगह के लिए छोड़ा जाएगा. इस



तरह इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में मेट्रो का प्रावधान कर इंदौर को पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का प्लान किया गया है. 19 किलोमीटर लंबी होगी सड़क - यह सड़क 13 सौ हेक्टेयर जमीन पर बनाई जाएगी. उक्त सड़क 75 मीटर चौड़ी और 19

किलोमीटर लंबी बनेगी. इसके लिए 17 गज की जमीन ली जा रही है. सड़क के दोनों ओर 300 मीटर की जमीन भी अधिग्रहित होगी, जिसमें होटल्स, मॉल और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस खुलेंगे. किसानों को विकसित प्लाट भी - ध्यान रहे कि

डीपीआर में मेट्रो का प्रावधान

एमपीआईडीसी की बहुचर्चित इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना का जो ड्राफ्ट बनाया गया है, उसमें 75 चौड़ी सड़क के बीच में 3.6 मीटर जमीन छोड़ी गई है. उक्त 3.6 मीटर जमीन को मेट्रो के पियर खड़े करने के लिए छोड़ने का उल्लेख है. सड़क निर्माण के डी मुख्य कैरेज के बीच चार लेन का प्रस्ताव है, लेकिन शुरू में यह तीन लेन ही बनाई जाएगी. इसकी वजह यह है कि मेट्रो रेल लाइन निर्माण के दौरान सड़क का एक हिस्सा दोनों तरफ खराब होगा. एमपीआईडीसी ने निर्णय लिया है कि मेट्रो के पियर के पास वाली एक एक लेन सड़क मेट्रो लाइन का काम पूरा होने के साथ बनाई जाएगी.

इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क में किसानों को 20 प्रतिशत राशि नकद और बाकी 40 प्रतिशत राशि के विकसित प्लॉट दिए जाएंगे. इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क योजना कुल 13 सौ हेक्टेयर जमीन पर लागू की गई है, लेकिन सड़क 11 सौ हेक्टेयर पर ही बनेगी.

बाकी 2 सौ हेक्टेयर जमीन ग्रामीण क्षेत्रों की अभी शामिल नहीं की जा रही है. उक्त जमीन गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों के लिए रखी गई है. मेट्रो के अफसर भी सक्रिय हुए - बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में मेट्रो का

प्रावधान करने के बाद एमपी मेट्रो के अधिकारियों ने भी गांधीनगर चौराहे से पीथमपुर तक मेट्रो लाइन के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है. इकोनॉमिक कॉरिडोर के टेंडर होने एक बाद मेट्रो भी डीपीआर तैयार करना शुरू कर देगा और मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा.

पहली जमीन की रजिस्ट्री सोमवार को - एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक हिमांशु प्रजापति ने बताया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क को मंजूरी मिल गई है. योजना में जिन किसानों ने पहले ही सहमति दे दी है, उनकी रजिस्ट्री पहले होगी. इसी के तहत सोमवार को ग्राम भंसेलाय के किसान की पहली रजिस्ट्री होगी, जिसका रॉलॉट पीजीन विभाग में बुक करा दिया है. इसके बाद लगातार किसानों की रजिस्ट्री का कार्य शुरू होगा, जो योजना की पूरी जमीन मिलने तक जारी रहेगा.

विकास प्राधिकरण बेगम बाग में लगातार कर रहा कार्रवाई



लीज निरस्ती के बाद कोर्ट पहुंच रहे मामले, जहां से नहीं मिल रही राहत

उज्जैन. महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर हरि फाटक ब्रिज के आगे भूखंड क्रमांक 19 पर अंगारा रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, जिसे मकान मालिक ने खुद ही तोड़ना प्रारंभ कर दिया है, और वह मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है, बचे हुए निर्माण को विकास प्राधिकरण हटाएगा.

नवभारत से चर्चा में विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि 30 से ज्यादा संपत्तियों की लीज निरस्त कर दी गई, जिनका आधिपत्य हमारे द्वारा धीरे-धीरे प्राप्त किया जा रहा है, क्योंकि कई मामले कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए हैं, जहां से कइयों को स्टे मिल गया था, जो-जो स्टे हटते जा रहे हैं, और वह संपत्तियां पुनः प्राप्त कर रहे हैं. और बाकी जिनके केस व चल रहे हैं उनका

फाटक ब्रिज के आगे अंगारा रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था, जहां पर बेज और नॉनबेज की शॉप संचालित की जाती थी. महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर यह संपत्ति भी विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई थी, लीज निरस्त होने के बाद कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली. ऐसे में विकास प्राधिकरण यहां बड़ी कार्रवाई करने वाला है, जिसके भय से अंगारा होटल संचालक ने निर्माण खुद ही हटाना प्रारंभ कर दिया.

केस हटने के बाद फिर होगी कार्रवाई - विकास प्राधिकरण ने बेगम बाग के जिन मकान दुकान मालिकों को नोटिस जारी किए थे, उनमें से कई मकान को प्राधिकरण स्वयं तोड़ चुका है, वहीं कुछ मकान - दुकानों को खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, ताकि ज्यादा नुकसान न हो. लीज समाप्त होने के बाद यह सारी संपत्ति विकास प्राधिकरण की हो गई है, और बाकी जिनके केस व चल रहे हैं उनका

फैसला होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी. 30 से अधिक संपत्तियों की लीज निरस्त - हरि फाटक मार्ग पर ब्रिज से आगे बेगम बाग और महाकाल मंदिर के नीलकंठ मार्ग के बीच में 30 से अधिक संपत्तियों को विकास प्राधिकरण लीज निरस्त करके वापस प्राप्त कर रहा है, यही कारण है कि दर्जन भर से अधिक कब्जाधारियों को नोटिस मिले थे, वह कोर्ट गए, वहां से किसी को भी सफलता नहीं मिली.

अनुमति आवासीय और चला रहे हैं होटल - उक्त मकान मालिकों ने लीज नवीकरण नहीं कराया. आवासीय प्रॉपर्टी पर व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी. होटल और होमस्टे बना दिए. प्रॉपर्टी के टुकड़े-टुकड़े करके दूसरों को बेच दिया और इस तरह की कई और भी शिकायत चल रही, जिनकी जांच कराई गई तो बड़ा मामला सामने आया.

जल्द होगी आगे की कार्रवाई - यह अच्छी बात है कि अंगारा सहित कुछ और मकान मालिक स्वयं के हाथों से कब्जा हटा रहे हैं, ताकि ज्यादा उनका नुकसान न हो. जो सामान निकलना चाहते हैं अपने मकान, दुकान होटल से निकाल सकते हैं. विकास प्राधिकरण जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगा. - संदीप सोनी, सीईओ, यूडीए

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित पर्यटन भवन, भद्रभद्रा रोड, भोपाल-462003 फोन नं. : +91-755-4027100, 2774340/42, www.mpstdc.com

क्रमांक 301/वात्रिकी/पविनि/25 दिनांक 07.08.2025

निविदा सूचना				
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है।				
क्र.	नि.सू. क्र./सिस्टम आई.डी./कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि रु. लाख में		
1	139/2025_STDC_442913_1/मालवा रिसोर्ट मांडू जिला धार में सोविनिचर शॉप का निर्माण आंतरिक विद्युत कार्य सहित। (03 माह)	13.61		
2	140/2025_STDC_442914_1/सैलानी आइलेण्ड रिसोर्ट ओंकारेश्वर जिला खण्डवा में सोविनिचर शॉप का निर्माण आंतरिक विद्युत कार्य सहित। (03 माह)	13.61		

वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि 22.08.2025 समय सायं 05:00 बजे तक निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/121475/2025 कार्यपालन यंत्री



स्वदेशी उत्पादन की राह पर मध्य प्रदेश

₹ 603 करोड़ से अधिक निवेश की औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण तथा आशय पत्र वितरण

₹ 208 करोड़ से अधिक के औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा






नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

उद्योगपतियों से संवाद

8 अगस्त, 2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे औद्योगिक क्षेत्र तामोट जिला रायसेन मध्य प्रदेश


